जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 29 संख्याः 251 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 14 जुलाई, 2022 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

खाद्य संकट और खाद्य सुरक्षा विश्व की दो प्रमुख समस्याएं हैं, तथापि, हजारों सालों से इंसान द्वारा उगाई जा रही एक फसल जल्दी ही दोनों समस्याओं को खत्म कर सकती है और इसके लिए बेहद मूल्यवान मीठे पानी की भी जरूरत नहीं है। मैक्रोएल्जी, जिसे सामान्यतया सीवीड कहा जाता है, एक सस्टेनबल क्रॉप के रूप में तेजी से विश्व भर के लोकप्रिय हो रही है। क्योंकि, एक तो पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव कम होता है दूसरा, इसमें पौष्टिक तत्व भी प्रचुर मात्रा में हैं। अमेरिका में सीवीड फार्मिंग, अब सबसे तेजी से बढ़ रहा एक्वाकल्चर सैक्टर है। पैसिफिक नॉर्थ वैस्ट, न्यू इंग्लैण्ड और अलास्का में पानी के अंदर इसके दर्जनों फार्म हैं। वर्ष 1950 से 2019 के बीच विश्व भर में सीवीड का उत्पादन 34.7 हजार टन से बढ़कर 34.7 मिलियन टन हो गया है। यह नाटकीय वृद्धि, कॉसमैटिक्स और टूथपेस्ट से लेकर वैकल्पिक प्लास्टिक, जैसे बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ आदि में सीवीड के वृहत् उपयोग को दर्शाती है। तथापि, विश्व की भूख मिटाने में भी इसकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यू.एन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के वरिष्ठ सलाहकार विन्सैंट डुमाइज़ल, जिन्होंने हाल ही में ''द सीवीड रिवोल्यूशन'' किताब लिखी है, का कहना है कि, ''केवल दो प्रतिशत महासागर में फार्मिंग करके हम 12 अरब लोगों की प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकते हैं।'' सीवीड में प्रोटीन भारी मात्रा में है लेकिन फैट व कार्बोहाइट्रेट कम है और यह वाइटमिन्स, ज़िंक व आयरन से भरपूर है। उन्होंने इसे सी फॉरैस्ट की संज्ञा दी। सीवीड की 12,000 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है और सभी खाने योग्य हैं। सीवीड के तीन समूह हैं- लाल, हरा और भूरा। भूरे रंग वाले समूह में सी कैल्प शामिल हैं जो सबसे बड़ी व सबसे आम प्रकार की सीवीड है तथा अंडर वॉटर सी फॉरैस्ट में भारी तादाद में मिलती है। इतना ही नहीं, सीफॉरैस्टेशन के लिए खाद, मीठे पानी आदि की जरूरत भी नहीं होती है। डुमाइज़ल ने कहा, अगर मवेशियों को सोया की बजाए सीवीड आधारित भोजन खिलाया जाए तो मीथेन गैस के उत्सर्जन में 90 प्रतिशत कम किया जा सकता है। इसके अलावा सीवीड से खाद्य संकट से जूझ रहे लोगों को पर्याप्त पोषण दिया जा सकता है। समुद्र के तटवर्ती समुदायों के लिए भी सीवीड फार्मिंग आय का एक विकल्प है क्योंकि अब इन स्थानों पर फिशिंग कम हो रही है।

श्रीलंका अकाल की ओर अग्रसर?

इसलिये देश के लिए पहली प्राथमिकता है, आई.एम.एफ. से किसी तरह से छोटा-मोटा ऋण प्राप्त करके खाने की सामग्री व पैट्रोल आयात किया जा सके

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली, 13 जुलाई। जब श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़ कर भाग गये तथा प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे अन्तरिम राष्ट्रपति बने गये तो बुधवार को यह देश घोर अराजकता की स्थिति में पहुँच गया।

श्रीलंका में सरकार नाम की शायद ही कोई चीज है तथा पदासीन अन्तरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने सेना से कहा है कि वह देश में पुनः व्यवस्था की स्थिति लाये। लेकिन शायद ही ऐसा कोई संकेत नज़र आ रहा है कि ऐसा हो रहा हैं।

अगर स्थिति में जल्दी ही स्थायित्व नहीं आता तथा अगर राजनैतिक अस्थिरता के फलस्वरूप हिंसा बढ़ती जाती है, तो श्रीलंका में एक आभासी स्थायित्व एवं शान्ति लाने के विषय में भारत का कुछ गम्भीर निर्णय लेने पडेंगे। ऐसी सम्भावना और भी ज्यादा दिखाई दे रही है कि श्रीलंका में खासतौर से खाद्य एवं ईंधन सहित, जरूरत की

- श्रीलंका में संकट की शुरुआत तब से हुई, जब से देश का संसदीय ढांचा बदलकर नई व्यवस्था लागू की गई, जिससे राष्ट्रपति में सर्वाधिक पावर निहित हो गई।
- वॉर-हीरो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने, तथा व्यक्तिगत भ्रष्टाचार व परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप सरेआम लगने लगे।
- श्रीलंका पुराने पार्लियामैन्टरी सिस्टम पर लौटना चाहता है, पर यह दूरगामी रणनीति है, तथा संविधान में परिवर्तन करके लायी जा सकती है।
- पर, सब दूर की बाते हैं, फिलहाल तो, जनता को भोजन कैसे उपलब्ध हो, तथा एम्बुलैंस आदि कैसे चलें, यह बड़ा संकट है।

अत्यावश्यक चीजों का घोर अभाव हो जाये।

श्रीलंका के कुछ अर्थशास्त्रियों ने ऐसी आंशका व्यक्त की है कि आगामी दो तीन महीनों में ऐसी स्थिति आ सकती हैं।

पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बारे में यह कहा जाता है कि वे युद्ध के नायक के रूप को त्याग कर एक ऐसे नापसन्द राजनेता के रूप में आ गये थे, जिसने कटुता उत्पन्न कर रहे तमिल पृथकतावादी आन्दोलन का सफाया करके, देश को अव्यवस्था की स्थिति में पहुँचा दिया तथा अपनी जेबें भरने में लगे रहे।

ऐसा व्यापक मान्यता है कि गोटाबाया राजपक्षे सरकार पूरी तरह भ्रष्ट थी तथा राजपक्षे के पूरे परिवार के हाथ तिजोरियों में रहते थे, जिसके फलस्वरूप, वे जनता का विश्वास खो चुके थे।

श्रीलंका में सरकार की संरचना में सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या यह थी कि सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित थीं। श्रीलंका सरकार मंत्री मण्डलीय प्रारूप वाली सरकार से हटकर, राष्ट्रपति प्रारूप वाली सरकार के रूप में आ गई थी।

अब माँग यह है कि सरकार का ढ़ाँचा बदले तथा यह राष्ट्रपति सरकार वाले प्रारूप से मन्त्रिमण्डल सरकार वाले प्रारूप में आये तथा पदासीन राष्ट्रपति की अबाधित एवं स्वच्छन्द शक्तियों पर नियन्त्रण रहे। विपक्षी दल एवं अन्य राजनैतिक समूह इस दिशा में काम कर रहे हैं कि श्रीलंका में यथाशीघ्र संविधान परिवर्तन/संशोधन हो।

लेकिन, यह एक दीर्घकालीन लक्ष्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश कुमार व लालू को ढलता सूरज मान भाजपा पंख पसारने की तैयारी में जुटी

जैसा कि विदित ही है, भाजपा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तो है, पर राज्य में अभी तक पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पायी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। भाजपा और जे.डी.यू. के बीच सत्ता संघर्ष बिहार में एक निर्णयात्मक चरण में पहुंच गया लगता हैं।

नीतीश कुमार ने जब से चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से उनकी गठबंधन सहयोगी एवं राज्य विधानसभा में अधिक सदस्य संख्या वाली भाजपा के साथ उनकी पार्टी के समीकरण संकटपूर्ण रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत से वर्ष 1857 में स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर का किला मुक्त कराने के सम्मान में भाजपा ने गत अप्रैल माह में महा उत्सव की तैयारियां की थीं और जे.डी.यू. को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। जे.डी.यू. अपनी ओर से भाजपा को राज्य की जातिगत जनगणना जैसे पेचीदा मुद्दों पर घेरने की कोशिश करती रही हैं।

- पर अब विस्तार का उपयुक्त समय मानते हुए, भाजपा ने प्रदेश में एक के बाद एक आम सभाएं आयोजित करने की योजना बनाई है।
- किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एस.सी. मोर्चा, एस.टी. मोर्चा के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है पटना में, जिसे पार्टी अध्यक्ष नड्डा व राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष संबोधित करेंगे।
- भाजपा ने प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करके, उपयुक्त जात/जाति के नेताओं को वहां की जिम्मेवारी सौंपी है।

जे.डी.यू. और लालू प्रसाद की आर.जे.डी. के बीच सम्भावित मेल मिलाप की खबरों के बीच बिहार में आगामी महीनों में एक बड़े बदलाव की संभावनाए बहुत ज्यादा हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ए.आई.एम.आई.एम. के पांच में चार विधायकों को तोड़ने में आर.जे.डी. को मिली सफलता के बाद भाजपा का फोकस कांग्रेस के विधायकों की अच्छी खासी संख्या को स्वयं में शामिल करने के विकल्प पर है। असदुद्दीन इसके साथ ही जे.डी.यू. में विभाजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा रहा हैं।

इसे लोहा गर्म हो तब प्रहार किए जाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि भाजपा ने कई राज्यव्यापी मीटिंग्स की योजना बना रखी हैं। भाजपा ने राज्य के समूचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 28 और 29 जुलाई को दो दिवसीय "प्रवास" आयोजित करने का निर्णय लिया हैं।

इसके बाद पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की 30 और 31 जुलाई को दो दिवसीय संयुक्त मीटिंग होगी। पटना में आयोजित होने वाली एक मीटिंग के लिए किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एस.सी.मोर्चा, एस.टी.मोर्चा अथवा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा हैं। मीटिंग को पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और भाजपा महासचिव बी.एल. संतोष संबोधित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ई.डी. डायरैक्टर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवाकाल में गत वर्ष 17 नवम्बर को दिए गए एक साल के

- ई.डी. डायरैक्टर संजय कुमार मिश्रा को एक साल का कार्यकाल विस्तार देने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

एक्सटैंशन को चुनौती देने वाली एक याचिका को लिस्ट करने का बुधवार को निर्णय लिया। इस याचिका में एक वकील ने कोर्ट का ध्यान उसके 8 सितम्बर के एक आदेश की ओर आकृष्ट किया है जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृति के बाद अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार सिर्फ अपवाद स्वरूप ही किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जो दिखता है, वो बिकता हैं'

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। राहुल गांधी ने ऐसा फिर कर दिया है। एक निजी दौरे पर कथित रूप से यूरोप जाकर उन्होंने इस आम धारणा को मजबूत कर दिया है कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारियों से बचता है, उन्हे यह भी पता नहीं है कि वे स्वयं को किस रूप में देखते हैं, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले एक नेता या एक ऐसा राजनेता जो गंभीरता से प्रयास ना करने के बावजूद सत्ता का लोभी है।

उनका नवीनतम विदेश दौरा कांग्रेस पार्टी की गुरुवार को आयोजित हो रही मीटिंग से थोड़ा पहले ही हुआ है। इस मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पार्टी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में लगे राजनीतिक झटकों के बाद हो रही है। पार्टी के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उसके अध्यक्ष के विकल्प पर मंथन होने जा रहा है। यह ऐसा पद है जिसे वर्ष 2019 में लोक सभा चुनावों की हार के कारण राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी संभाले हुए है।

यह ध्यान देने योग्य है कि गुरुवार की मीटिंग के लिए पार्टी के सभी

- राहुल गांधी के एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकलने से, जनता व पार्टी असमंजस में है कि, राहुल गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, व ऐसे दूल्हा जिसे विवाह में कोई रूचि नहीं।

महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है।

क्या राहुल पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उनकी गैर मौजूदगी की वजह से यह भी स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को जो बात स्पष्ट है, वह यह कि ऐसी पार्टी, जिसका चेहरा अब भी राहुल गांधी हैं, वह अटकाव की स्थिति में है और वह स्थिति चरम सीमा पर है।

जन धारणा ये है कि राहुल गांधी बिना पतवार वाले एक ऐसे जहाज का प्रतीक बन गए हैं जो अपने वर्तमान दलदल से बाहर निकलने से बार-बार इन्कार करता है। गुरुवार की मीटिंग में 2 अक्टूबर से शुरु हो रही "भारत जोड़ो यात्रा" की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। इस मीटिंग से राहुल गांधी की अनुपस्थिति से नेतृत्व के प्रश्न की अटकलों को और मसाला मिलना तय है।

भाजपा ने राहुल गांधी की हाल की विदेश यात्राओं की आलोचना की है। इनमें मई माह की आलोचना की है। इनमें मई माह की शुरुआत में हुई एक यात्रा भी शामिल है, जब उन्हें काठमांडू के एक नाइट क्लब में देखा गया था। इसकी तस्वीरें भाजपा समर्थकों द्वारा जारी की गई थीं लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि एक पत्रकार की शादी में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने में क्या गलत है।

काठमांडू का दौरा अन्य राज्यों के अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के तुरंत बाद किया गया था। राहुल गांधी ने तब यूरोप का दौरा भी किया था। उन चुनावों से पूर्व वह दिसम्बर माह में इटली चले गए थे और जनवरी के मध्य में लौटे।

वे मई के उत्तरार्द्ध में भी विदेश गये थे। इंग्लैंड के केम्ब्रिज की इस यात्रा पर भी, भाजपा नेताओं ने राजनैतिक स्वीकृति लेने के उनके इनकार पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राम सेतु

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस बात के लिये सहमत हो गया कि भाजपा नेता डॉ. सुब्रमन्यम स्वामी की उस याचिका की सुनवाई 26 जुलाई को की जायेगी, जिसमें उन्होंने केन्द्र को ऐसे निर्देश दिये

- राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मसले पर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, इस पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी।

जाने की माँग की है कि वह "राम सेतु" को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करे।

राम सेतु, जिसे आदम के पुल के नाम से भी जाना जाता है, लाइमस्टोन शोल्स का एक शृंखला है, जो तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्व तट के पास स्थित पम्बन द्वीप से श्रीलंका के उत्तर-पश्चिम तट के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

"रिन्युएबल एनर्जी" कंपनियों को भुगतान का मामला अब सुलझेगा?

तीन साल से "रिन्युएबल एनर्जी" कंपनियां सरकारी ग्रिड में बिजली दे रही थीं, परंतु इसके एवज में कोई भुगतान नहीं मिल रहा था

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 13 जुलाई। प्रदेश में "रिन्युएबल एनर्जी सर्टिफिकेट" (आर.ई.सी.) स्कीम के तहत सोलर तथा विंड मिल से अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनियों और संस्थाओं द्वारा राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर मामले का राजस्थान हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश एस.एस. श्रीवास्तव और न्यायाधीश शुभा मेहता ने मामले की सुनवाई करते हुए इस केस को अगले माह पांच तारीख को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और साथ ही कहा कि न्यायालय राज्य सरकार या किसी अन्य पार्टी को इस मामले में किसी भी कारण से स्थगन के आदेश जारी नहीं करेगा।

जैसा कि विदित है कि आर.ई.सी. स्कीम के तहत राज्य व केन्द्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए कई कम्पनियों और संस्थानों को प्रोत्साहित किया। इन कम्पनियों को राज्य सरकार ने अपनी अक्षय ऊर्जा को 2012-13 की नीति के तहत आश्वासन दिया था कि सभी संस्थाओं और कम्पनियों को 25 वर्ष तक सतत् लाभ यानि स्थायी "रेट ऑफ रिटर्न" पहुंचायेगी ताकि इन कम्पनियों को घाटा न हो। राज्य सरकार की अक्षय ऊर्जा नीति में समाहित था कि राज्य सरकार अगले 25 वर्ष तक इन कम्पनियों से ऊर्जा स्थाई दर पर खरीदेगी ताकि उन्हें नुकसान ना हो।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-13 में सोलर पैनलों में बनने् वाली अक्षय ऊर्जा को मार्केट में 16 से 18 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बेचा जाता था। परंतु वर्ष 2019 के बाद से टैक्नोलॉजी में सुधार और सोलर पैनलों के निर्माण में लागत कम होने की वजह से सोलर पैनलों से बन रही अक्षय ऊर्जा की प्रति युनिट दर में भारी गिरावट आई। यहां तक कि 2019 में राज्य सरकार को "ओपन टैण्डरों" में "सोलर फार्म्स" में 2.86 रुपये प्रति यूनिट की दर पर उर्जा मिल रही थी।

- हाई कोर्ट भी अभी तक "रिन्युएबल एनर्जी" कंपनियों और सरकार के बीच समझौता होने की संभावना पर कार्य कर रहा था और तारीखों पर तारीख दिये जा रहा था।
- पर अब हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि, 5 अगस्त को इस मामले पर दो-तीन दिन लगातार सुनवाई कर अपना निर्णय देगा।
- रिन्युएबल एनर्जी कंपनियों में हाई कोर्ट के इस आदेश से हर्ष और उत्साह दिख रहा है।

"सोलर तथा विंड मिल से निर्मित ऊर्जा "ओपन मार्केट" में सस्ते दामों में मिल रही थी इस लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में आर.ई.सी. स्कीम के तहत अक्षय उर्जा क्षेत्र में निवेश कर चुकी कंपनियों से नया "पावर परचेज़ एग्रीमेंट" (पी.पी.ए.), यानि अक्षय उर्जा खरीदने की नयी दर, तय करना चाहती थी। परंतु समझौते नहीं होने के कारण सरकार आर.ई.सी. स्कीम के तहत निवेश कर चुकी करीब 108 प्राईवेट तथा सरकारी संस्थाओं व कंपनियां पिछले तीन साल से बिजली उत्पादन के लिए कोई पैसा नहीं दे रही है।

वर्ष 2019 से इन 108 कंपनियों ने हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ याचिकायें दायर कर रखी थीं, क्योंकि सरकारी ग्रिड में बिजली डालने के बाद भी उन्हें सरकार पैसा नहीं दे रही है।

मंगलवार को भी राज्य सरकार ने कहा कि सरकार और सभी 108 संस्थाओं या कंपनियों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार आर..ई.सी. स्कीम के तहत सौर उर्जा बनाने वाली कंपनियों को 2.24 रुपये प्रति यूनिट की दर पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बालिका से रेप

श्रीगंगानगर, 13 जुलाई (कासं)। रायसिंहनगर इलाके के एक गांव में नानी के साथ स्कूल से घर लौट रही दस साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है।

रायसिंह नगर एस.एच.ओ. गणेश कुमार के अनुसार बच्ची रायसिंहनगर

- दस साल की यह बच्ची अपनी नानी के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, रास्ते में वह थोड़ा आगे निकल गई तो आरोपी युवक ने उसे घर छोड़ने की बात कह कर बाइक पर बिठा लिया और स्कूल के पास खंडहर में ले जाकर रेप किया।

इलाके के एक गांव में अपनी नानी के पास आई हुई थी। वह अपनी नानी के साथ अपने भाई की टीसी लेने के लिए स्कूल में गई थी। वहां से वापस लौटने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)